[2014] 10 एस.सी.आर. 426

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

बनाम

एसोसिएटेड ठेकेदार

(सिविल अपील संख्या 6691/2005)

सितंबर 10,2014

[आर.एम. लोढ़ा सीजेआई, कुरियन जोसेफ और आर.एफ. नरीमन, जेजे.]

माध्यस्थम् और सुलह अधिधियम, 1996:

धाराएँ 34, 42 – किस न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकारिता होगा -अभिनिर्धारित: "न्यायालय" उच्च न्यायालय होगा न कि जिला न्यायालय।

धारा 42 – प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित: अभिव्यक्ति " माध्यस्थम् करार के संबंध में" यह स्पष्ट करती है कि धारा 42 माध्यस्थम् कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या अधिनियम के भाग- I के तहत अधिनिर्णय घोषित होने के बाद किए गए सभी आवेदनों पर लागू होगी।

धारा 42 – न्यायालय – तात्पर्य

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1. माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 के प्रयोजन के लिए "न्यायालय" उच्च न्यायालय होगा न कि जिला न्यायालय। यह मूल

अधिकारिता का प्रयोग करने वाली सर्वोच्च न्यायालय है जिसे माध्यस्थम् करार से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए चुना गया है। [पैरा 15] [436-एच; 437-सी]

कार्यकारी अभियंता, सड़क विकास धारा सं.III, पनवेल और अन्य बनाम अटलांटा लिमिटेड एआईआर 2014 एससी 1093: 2014 एससीआर 507-निर्भरता।

2. धारा 11 के आवेदनों को परिभाषित "न्यायालय" के समक्ष नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, जैसा भी मामला हो, या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर धारा 42 लागू नहीं होगी। [पैरा 16] [439-ई, एफ]

पांडे एंड कंपनी बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य (2007) 1 एससीसी 467: 2006 (8) पूरक एससीआर 997; पी.आनंद गजपति राजू और अन्य बनाम पी.वी.जी. राजू (मृत) और अन्य (2000) 4 एससीसी 539: 2000 (2) एससीआर 684; पी.कासिलिंगम और अन्य बनाम पी.एस.जी. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्य (1995) पूरक 2 एससीसी 328: 1995 (2) एससीआर 1061; रोडेमाडन इंडिया लिमिटेड बनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो सेंटर लिमिटेड (2006) 11 एससीसी 651; एस.बी.पी.एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य (2005) 8 एससीसी 618: 2005 (4) पूरक एससीआर 688; मध्य प्रदेश राज्य बनाम सेठ और स्केल्टन (पी) लिमिटेड (1972) 1 एससीसी 702: 1972 (3) एससीआर 233-निर्भरता।

गुरु नानक फाउंडेशन बनाम रतन सिंह एंड संस (1981) 4 एससीसी 634: 1982 (1) एससीआर 842; नेशनल एल्यूमीनियम कं. लिमिटेड (2008) 6 एससीसी

732: 2008 (3) एससीआर 1124; गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम कृष्णा ट्रैवल एजेंसी (2008) 6 एससीसी 741 - संदर्भित किया गया।

3. धारा 2(1)(ई) में एक विस्तृत परिभाषा है जो केवल किसी जिले में मूल अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय या राज्य में मूल सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय को चिह्नित करती है, और माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 के भाग-1 के उद्देश्य के लिए किसी अन्य न्यायालय को "न्यायालय" के रूप में चिह्नित नहीं करती है। " माध्यस्थम् करार के संबंध में" अभिव्यक्ति यह स्पष्ट करती है कि धारा 42 अधिनियम 1996 के भाग-1 के तहत माध्यस्थम कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या अधिनिर्णय दिए जाने के बाद किए गए सभी आवेदनों पर लागू होगी। तथापि, धारा 42 केवल भाग-1 के अधीन किए गए आवेदनों पर लागू होती है यदि वे परिभाषित न्यायालय में किए जाते हैं। चूँकि धारा 8 के तहत किए गए आवेदन न्यायिक प्राधिकारियों को किए जाते हैं और चूंकि धारा 11 के तहत आवेदन मुख्य न्यायाधिपति या उनके नामित व्यक्ति को किए जाते हैं, इसलिए न्यायिक प्राधिकारी और मुख्य न्यायाधिपति या उनके नामित व्यक्ति, जो परिभाषित न्यायालय नहीं हैं, ऐसे आवेदन धारा 42 के बाहर होंगे। धारा 9 के आवेदन न्यायालय में किए गए आवेदन हैं और धारा 34 के माध्यस्थम् अधिनिर्णयों को अलग करने के लिए आवेदन ऐसे आवेदन हैं जो धारा 42 के भीतर हैं। किसी भी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय धारा 2(1)(ई) के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" नहीं हो सकता है, और चाहे सर्वोच्च न्यायालय माध्यस्थ की नियुक्ति के बाद अधिकारिता रखता है या नहीं रखता है, आवेदन या तो राज्य में मूल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या जिले में मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष किए गए पहले आवेदन का पालन करेंगे। धारा 42 माध्यस्थम् कार्यवाही समाप्त होने के बाद किए गए आवेदनों पर लागू होगी बशर्ते वे भाग-I के तहत किए गए हों। यदि किसी ऐसे न्यायालय में पहला आवेदन किया जाता है जो न तो

किसी जिले में मूल अधिकारिता का प्रधान न्यायालय है या किसी राज्य में मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय है, तो ऐसा आवेदन धारा 42 के बाहर होगा। इसके अलावा, विषय वस्तु अधिकारिता के बिना न्यायालय में किया गया आवेदन धारा 42 के बाहर होगा। [पैरा 25] [445-बी-एच; 446-ए-बी]

कुंभा मावजी बनाम डोमिनियन ऑफ इंडिया (1953) एससीआर 878; एफसीआई का प्रतिनिधित्व प्रबंध निदेशक और अन्य अन्न बनाम ए.एम. अहमद एनी ककंपनी द्वारा एमडी और अन्य (2001) 10 एस. सी. सी. 532; नेयसर इंडिया लिमिटेड बनाम जीएनबी सिरेमिक लिमिटेड (2002) 9 एससीसी 489; जतिंदर नाथ बनाम चोपड़ा लैंड डेवलपर्स प्रा.लिमिटेड (2007) 11 एससीसी 453 2007 (3) एससीआर 545; राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम यूनिवर्सल पेट्रोल केमिकल लिमिटेड (2009) 3 एससीसी 107: 2009 (1) एससीआर 138; स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2013 (9) एससीसी 32: 2013 (7) एससीआर 581; एचबीएम प्रिंट लिमिटेड बनाम स्कैनट्रांस इंडिया (प्रा.) लिमिटेड (2009) 17 एससीसी 338-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

2000 (2) एससीआर 684	भरोसा किया गया	पैरा 12
1995 (2) एससीआर 1061	भरोसा किया गया	पैरा 14
2014 एससीआर 507	संदर्भित	पैरा 15
(2006) 11 एससीसी 651	भरोसा किया गया	पैरा 16
2005 (4) पूरक एससीआर 688	भरोसा किया गया	पैरा 16
2006 (8) पूरक एससीआर 997	भरोसा किया गया	पैरा 16

1972 (3) एससीआर 233	भरोसा किया गया	पैरा 19
1982 (1) एससीआर 842	संदर्भित	पैरा 19
(2004) 1 एससीसी 540	संदर्भित	पैरा 19
2008 (3) एससीआर 1124	संदर्भित	पैरा 19
(2008) 6 एससीसी 741	संदर्भित	पैरा 19
(1953) एससीआर 878	संदर्भित	पैरा 21
(2001) 10 एससीसी 532	संदर्भित	पैरा 22
(2002) 9 एससीसी 489	संदर्भित	पैरा 22
2007 (3) एससीआर 545	संदर्भित	पैरा 22
2009 (1) एससीआर 138	संदर्भित	पैरा 22
2013 (7) एससीआर 581	संदर्भित	पैरा 22
(2009) 17 एससीसी 338	संदर्भित	पैरा 23

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 691/2005

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सी.ओ. संख्या 3938/2004 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.04.2005 से उत्पन्न।

साथ में

सी.ए. संख्या 4808/2013

अनीप सचथे, शगुन मट्टा, साकार सरदाना, अपीलार्थियों की ओर से।

प्रदीप घोष, देब प्रसाद मुखर्जी, नंदिनी सेन, सौम्या दत्ता (के. वी. भारती उपाध्याय के लिए), प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

आर.एफ. नरीमन, न्यायाधिपति. 1. यह मामला इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के 7 अप्रैल, 2010 के संदर्भ आदेश द्वारा तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया है। सन्दर्भ आदेश इस प्रकार हैः

> "इस अपील में, निर्णय के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद संक्षिप्त में 'अधिनियम') की धारा 34 के तहत आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकारिता किस न्यायालय के पास होगा।
>
> 2. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास रंजन भट्टाचार्य ने नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेस्टील एंड फैब्रिकेशंस (पी) लिमिटेड और अन्य (2004) 1 एससीसी 540, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन (2008) 6 एससीसी 732, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम एच.पी. बिस्वास एंड कंपनी (2008) 6 एससीसी 740 और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम कृष्णा ट्रैवल एजेंसी (2008) 6 एससीसी 741 के मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया। उनके इस निवेदन के समर्थन में कि यह केवल प्रधान सिविल न्यायालय है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(ई) में परिभाषित किया गया है, जो अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 34

के तहत एक आवेदन पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है।

3. दूसरी ओर प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप घोष ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेंट में धारा 12 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए माध्यस्थम् कार्यवाही शुरू होने से पहले अधिनियम की धारा 9 के तहत एक अंतरिम आदेश पारित किया था और अधिनियम की धारा 42 के आधार पर, यह केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय है जिसके पास अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार होगा। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने जिंदल विजयनगर स्टील (जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड) बनाम जिंदल प्रैक्सायर ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड (2006) 11 एससीसी 521 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

4. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का अध्ययन किया है, जो सभी दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय हैं। हमारी राय में, कानून को संदेह से परे स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किस न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 34 सपठित धारा 2(ई) और अधिनियम की धारा 42 सहित अन्य प्रावधानों के तहत अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकारिता होगा। इसलिए हम कानून के इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को एक वृहद पीठ के पास भेजते हैं।

5. इस मामले के कागजातों को एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष रखा जाए।

6. जब तक एक वृहद पीठ द्वारा अपील का निस्तारण नहीं किया जाता है, तब तक 17.05.2007 का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।"

2. इस मामले को तय करने के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैंः

1995-96 में पुलिस स्टेशन माल, जिला जलपाईगुरी, पश्चिम बंगाल में 3.625 किलोमीटर की श्रृंखला से तीस्ता-जलढाका मुख्य नहर की खुदाई और अस्तर के काम के निष्पादन के लिए प्रतिवादी संबद्ध ठेकेदारों और संबंधित अधीक्षण अभियंता के बीच एक वस्तु दर निविदा को विधिवत निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया था। उक्त वस्तु दर निविदा और अनुबंध के पैरा 25 में एक माध्यस्थम खंड था।

3. यहाँ प्रतिवादी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अंतरिम आदेशों के लिए माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने लेटर्स पेटेंट के धारा 12 के तहत अनुमति देने के बाद एक अंतरिम एकतरफा निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। यह आदेश समय-समय पर तब तक जारी रहा जब तक कि 10 दिसंबर, 1998 के एक आदेश द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो गई। इस बीच, माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में, न्यायाधीश बी. पी. बनर्जी (सेवानिवृत्त) को पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक माध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य द्वारा दायर एक रिकालिंग आवेदन 20 जनवरी, 2000 को खारिज कर दिया गया था।

4. अंतरिम एक तरफा निषेधाज्ञा की पुष्टि करते हुए 10 दिसंबर, 1998 के आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी। 5 जुलाई, 2000 को अपील दायर करने में विलम्ब को माफ कर दिया गया और 20 जुलाई, 2000 को खण्ड पीठ द्वारा अंतरिम

आदेश पर रोक लगा दी गई। हालाँकि, माध्यस्थ को उनके समक्ष कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा गया था जो निर्बाध रूप से जारी रहेगी।

5. इस बीच, उच्च न्यायालय द्वारा माध्यस्थ के पारिश्रमिक और उसके भुगतान के संबंध में कई आदेश पारित किए गए। मध्यस्थता की कार्यवाही 30 जून, 2004 को एक अधिनिर्णय में समाप्त हुई, जिसके द्वारा दावेदार को 1 जुलाई, 1998 से अधिनिर्णय की तारीख तक 10% ब्याज के साथ 2,76,97,205.00 रुपये की राशि प्रदान की गई। यदि चार महीने के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस पर प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज लगेगा। 50,000/- रुपये की लागत भी प्रदान की गई। प्रतिवादी के प्रतिदावे खारिज कर दिये गये।

6. 21 सितंबर, 2004 को पश्चिम बंगाल राज्य ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में विद्वान जिला न्यायाधीश के प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष माध्यस्थम् अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया। 6 अक्टूबर, 2004 को जलपाईगुड़ी के विद्वान जिला न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर प्रतिवादी को 4 जनवरी, 2004 को या उससे पहले उपस्थित होने और अपनी लिखित आपत्तियां दायर करने का निर्देश दिया। 10 दिसंबर, 2004 को प्रत्यर्थी ने जलपाईगुड़ी में विद्वान जिला न्यायाधीश की न्यायालय की अधिकारिता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक आवेदन दायर किया। 11 अप्रैल, 2005 के विवादित फैसले से कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 227 के तहत याचिका को स्वीकार कर लियाः

> "तदनुसार, मैं अभिनिर्धारित करता हूँ कि चूंकि पक्षकारों ने पहले से ही उक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाली विभिन्न पूर्व कार्यवाही के संबंध में अपने सामान्य मूल सिविल अधिकारिता में इस न्यायालय के अधिकारिता में प्रस्तुत किया था, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है,

इसलिए जलपाईगुड़ी में विद्वान जिला न्यायाधीश की न्यायालय की अधिकारिता को उक्त अधिनियम की धारा 42 के तहत खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि यह न्यायालय अपने सामान्य मूल सिविल अधिकारिता में एकमात्र ऐसा न्यायालय है जो उक्त अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है। इस प्रकार, पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार आक्षेपित नोटिस को अपास्त किया जाता है।"

7. इस आदेश के खिलाफ दायर एक एसएलपी में, पश्चिम बंगाल राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अनीप सचथे ने तर्क दिया कि चूंकि धारा 9 के तहत किया गया आवेदन स्वयं अधिकारिता के बाहर था, इसलिए माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 42 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि खण्ड पीठ ने धारा 9 के तहत पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगाने का कारण यह था कि यह प्रथमदृष्टया आश्वस्त था कि इस मामले में उच्च न्यायालय का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के. घोष ने तर्क दिया कि खंड 12 को पहले ही अनुमति दे दी गई थी और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 22 जुलाई, 1998 के अंतरिम एकतरफा आदेश के बाद कई आदेश पारित किए गए थे। वास्तव में, किसी भी न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसने अधिकारिता पर फैसला सुनाया हो, और इसलिए, धारा 42 अनिवार्य रूप से मामले के तथ्यों पर लागू होगी।

9. चूंकि मामला धारा 2(1)(ई) और धारा 42 पर एक आधिकारिक घोषणा के लिए हमारे पास भेजा गया है, इसलिए माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई) और धारा 42 को निर्धारित करना महत्वपूर्ण होगा जो निम्नानुसार हैः

“2(1)(ङ) “न्यायालय” से किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय भी है, जो माध्यस्थम् की विषय-वास्तु होने वाले प्रश्नों का, यदि वे वाद की विषय-वास्तु होते तो, विनिश्चय करने की अधिकारिता रखता, किन्तु ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से अवर श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है।

42. अधिकारिता- इस भाग के अन्यत्र या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वहां किसी माध्यस्थ करार की बाबत इस भाग के अधीन कोई आवेदन किसी न्यायालय में किया गया है तो वहां ऐसी माध्यस्थ कार्यवाहियों तथा उक्त करार से उदभूत होने वाले सभी पश्चातवर्ती आवेदनों पर इसी न्यायालय की अधिकारिता होगी और माध्यस्थम कार्यवाहियों उसी न्यायालय में की जाएगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी।“

10. धारा 2(1)(ई) की उत्पत्ति 1940 के अधिनियम की धारा 2(सी) में हुई थी। धारा 42 की उत्पत्ति 1940 के अधिनियम की धारा 31(4) में हुई थी। 1940 के अधिनियम की ये धाराएँ इस प्रकार हैंः

“2(ग) "न्यायालय" का अर्थ एक सिविल न्यायालय है जिसके पास सन्दर्भ के विषय-वस्तु से सम्बंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार है, यदि वह किसी मुक़दमे का विषय-वास्तु रहा हो, लेकिन धारा 21 के तहत माध्यस्थम् कार्यवाही के उद्देश्य के अलावा, एक लघु कारण न्यायालय शामिल नहीं है;

31(4) इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कहीं भी कुछ भी शामिल होने के बाबजूद, जहाँ किसी भी सन्दर्भ में इस अधिनियम के तहत कोई आवेदन उस पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय में किया गया है, अकेले उस न्यायालय को माध्यस्थम कार्यवाही और उस संदर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदनों पर अधिकार क्षेत्र होगा और माध्यस्थम् कार्यवाही उस न्यायालय में और किसी अन्य न्यायालय में नहीं की जाएगी।”

11. यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 42 अपने पूर्ववर्ती धारा के लगभग समान शब्दों में है, सिवाय इसके कि "किसी भी संदर्भ में" शब्दों को "माध्यस्थ करार के संबंध में" व्यापक अभिव्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। यह भी ध्यान दिया जाएगा कि धारा 42 में "इसे स्वीकार करने के लिए सक्षम न्यायालय में अभिव्यक्ति की गई है", अब नहीं है। ये दोनों परिवर्तन कुछ महत्व के हैं जैसा कि बाद में बताया जाएगा। धारा 42 एक गैर-अस्थाई धारा के साथ शुरू होती है जो माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 के भाग-I या उस समय लागू किसी अन्य कानून की धारा के साथ असंगत हो सकती है। " माध्यस्थम् करार के संबंध में" अभिव्यक्ति धारा 42 के दायरे को उन सभी मामलों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माध्यस्थम करार से संबंधित हैं। न्यायालयों में किए गए आवेदन जो अधिनियम के भाग-I के तहत माध्यस्थम् कार्यवाही से पहले, उसके दौरान या बाद में किए जाते हैं, सभी धारा 42 के दायरे में आते हैं। लेकिन इस धारा का एक अनिवार्य घटक यह है कि भाग-I के तहत एक आवेदन न्यायालय में किया जाना चाहिए।

12. माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 के भाग-1 में माध्यस्थ करार के संबंध में किए जा रहे विभिन्न आवेदनों पर विचार किया गया है। उदाहरण के लिए, धारा 8 के तहत एक न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन किया जा सकता है जिसके समक्ष

एक मामले में कार्रवाई की जाती है जो एक माध्यस्थ करार का विषय है। यह स्पष्ट है कि धारा 8 के तहत किए गए आवेदन न्यायालयों में होने की आवश्यकता नहीं है, और केवल इसी कारण से, ऐसे आवेदन धारा 42 के दायरे से बाहर होंगे। पी.आनंद गजपति राजू और अन्य बनाम पी.वी.जी. राजू (मृत) और अन्य, (2000) 4 एससीसी 539 में पैरा 8 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 8 के तहत आवेदन धारा 42 के दायरे से बाहर होंगे। हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं, लेकिन इस कारण से कि इस तरह के आवेदन "न्यायिक प्राधिकारियों" के समक्ष किए जाते हैं न कि "न्यायालयों" के समक्ष, जैसा कि परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, एक पक्ष जो धारा 8 के तहत आवेदन करता है, वाद का मास्टर के रूप में लागू नहीं होता है, लेकिन जहां भी 'कार्रवाई' दर्ज की गई हो, उसे जाना पड़ता है। इस प्रकार, धारा 8 के तहत एक आवेदन प्रकृति में परजीवी है -इसे केवल न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष दायर किया जाना है जिसके समक्ष किसी और द्वारा कार्यवाही दायर की जाती है। इसके अलावा, "न्यायिक प्राधिकारी" एक न्यायालय हो भी सकता है और नहीं भी। और जिस न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई की जा सकती है, वह मूल अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय या मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय नहीं हो सकता है। यह हमें अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के तहत "न्यायालय" की परिभाषा पर लाता है।

13. यह ध्यान दिया जाएगा कि 1940 के अधिनियम में निहित पूर्व परिभाषा में किसी भी सिविल न्यायालय की बात की गई थी, लेकिन 1996 के अधिनियम में परिभाषा "न्यायालय" को अपने सामान्य मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी जिले या उच्च न्यायालय में मूल अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय निर्धारित करती है। धारा 2(1)(ई) में आगे कहा गया है कि किसी न्यायालय में ऐसे

प्रधान सिविल न्यायालय या लघुवाद न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय शामिल नहीं होगा।

14. यह ध्यान दिया जाएगा कि परिभाषा एक संपूर्ण है क्योंकि यह "तात्पर्यित और सम्मिलित" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। यह सुस्थापित कानून है कि ऐसी परिभाषाएँ प्रकृति में संपूर्ण होने के लिए हैं – देखें पी. कासिंगम और अन्य बनाम पी.एस.जी. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अन्य, (1995) पूरक 2 एससीसी 348 पैरा 19 पर।

15. इस माननीय न्यायालय का एक नया निर्णय कार्यकारी अभियंता, सड़क विकास खंड सं. III, पनवेल और अन्य बनाम अटलांटा लिमिटेड, एआईआर 2014 एससी 1093 में यह विचार रखा कि धारा 2(1)(ई) में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 में निहित योजना से अलग एक योजना शामिल है। धारा 15 में सभी वादों को निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर करने की अपेक्षा की गई है। इस माननीय न्यायालय ने धारा 2(1)(ई) का अर्थ निकाला है और कहा है कि जहां कोई उच्च न्यायालय किसी जिले पर सामान्य मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता है, वहां उच्च न्यायालय को उस जिले में मूल अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय को प्राथमिकता दी जाएगी। उस मामले में, एक पक्ष ने धारा 34 के तहत जिला न्यायाधीश, ठाणे के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उसी दिन, विरोधी पक्ष ने अधिनिर्णय में निहित कुछ निर्देशों को दरकिनार करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इन परिस्थितियों में, यह निर्णय लिया गया कि धारा 42 के उद्देश्य के लिए "न्यायालय" उच्च न्यायालय होगा न कि जिला न्यायालय। इसके लिए कई कारण बताए गए थे। सबसे पहले, परिभाषा में उच्च न्यायालय को शामिल करना ही निरर्थक हो जाएगा यदि उपरोक्त निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जाना था, क्योंकि किसी जिले में मूल अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय हमेशा उच्च न्यायालय की तुलना में

निम्न श्रेणी का न्यायालय होता है, और ऐसा जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय की तुलना में निम्न श्रेणी का होने के कारण हमेशा उच्च न्यायालय को मामले पर निर्णय लेने से बाहर कर देता है। दूसरा, माध्यस्थम् अधिनियम के प्रावधान किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं कि यह मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला सबसे उच्च न्यायालय है जिसे माध्यस्थम् करार से उत्पन्न विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए चुना गया है। हम इस निर्णय में निहित तर्क से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

16. माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 11 के तहत किए गए आवेदनों के संबंध में भी यही स्थिति है। रोडेमेडन इंडिया लिमिटेड बनाम इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सेंटर लिमिटेड, (2006) 11 एससीसी 651 में, एस.बी.पी. और कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य, (2005) 8 एससीसी 618 में सात न्यायाधीशों की पीठ के बाद इस माननीय न्यायालय के एक नामित न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय के बजाय, धारा 11 में निहित मध्यस्थों को नियुक्त करने की शक्ति मुख्य न्यायाधिपति या उनके प्रतिनिधि को प्रदान की जाती है। वास्तव में, सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दियाः

> "13. यह सामान्य आधार है कि अधिनियम ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल अधिनियम को अपनाया है। लेकिन साथ ही, इसने मॉडल अधिनियम से कुछ विचलन किए हैं। धारा 11 मॉडल अधिनियम के अनुच्छेद 11 के स्थान पर है। मॉडल अधिनियम अनुच्छेद 11 के तहत "आवश्यक उपाय करने के लिए अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट न्यायालय या अन्य प्राधिकरण" से अनुरोध करने का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 11 में शब्द "मुख्य न्यायाधिपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था" हैं। इस तथ्य की कि न्यायलय के बजाय, मुख्य न्यायाधिपति को शक्तियां प्रदान की जाती हैं, क़ानून

के संदर्भ में सराहना की जानी चाहिए। अधिनियम में 'न्यायालय' को जिले के मूल अधिकारिता के प्रमुख सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें उच्च न्यायालय अपने सामान्य मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करता है। मूल अधिकारिता का प्रमुख सिविल न्यायालय आम तौर पर जिला न्यायालय होता है। भारत में सामान्य मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय बहुत अधिक नहीं हैं। अतः अधिकांश राज्यों में संबंधित न्यायालय जिला न्यायालय होगा। जाहिर है, संसद जिला न्यायालय को एक मध्यस्थ नियुक्त करने या अधिनियम की धारा 11 के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के अनुरोध पर विचार करने की शक्ति प्रदान नहीं करना चाहती थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 9 के तहत, मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थता से पहले, उसके दौरान या उसके बाद भी अंतरिम आदेश देने की शक्ति है। इसमें उस अधिनिर्णय को चुनौती देने की भी शक्ति है जो अंततः दिया जा सकता है। अधिनियम के निर्माताओं को निश्चित रूप से अधिनियम में 'न्यायालय' की परिभाषा के प्रति जागरूक माना जाना चाहिए। यह आसानी से विचार करना संभव है कि वे नहीं चाहते थे कि धारा 11 के तहत शक्ति जिला न्यायालय या मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय को प्रदान की जाए। जाहिरा तौर पर इरादा राज्य और देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और भारत के मुख्य न्यायाधिपति को शक्ति प्रदान करना था। इस तरह के प्रावधान का उद्देश्य अनिवार्य रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया में सबसे बड़ी विश्वसनीयता

जोड़ना है। यह तर्क कि मुख्य न्यायाधिपति को इस प्रकार प्रदान की गई शक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को भी नहीं सौंपा जा सकता है, केवल दूसरे को नामित करने की शक्ति के कारण नकार दिया जाता है। विधायिका का इरादा स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अधिनियम की धारा 11(6) के तहत शक्ति का प्रयोग संबंधित राज्य या देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी द्वारा किया जाए। यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन की प्रक्रिया के लिए अधिकतम अधिकार सुनिश्चित करने के लिए है।

18. यह सच है कि अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत शक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है, बल्कि यह भारत के मुख्य न्यायाधिपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को प्रदान की गई है। प्रधान न्यायाधीश के रूप में प्राधिकारी को निर्दिष्ट करने का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि यदि यह केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करना था, तो मामला उस न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया द्वारा शासित होगा, जिसमें अपील का अधिकार भी शामिल है और संसद स्पष्ट रूप से उस स्थिति से बचना चाहती थी, क्योंकि उद्देश्यों में से एक मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करना था। इसलिए, देश और राज्य में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी को मुख्य न्यायाधीशों के रूप में उनकी क्षमताओं में शक्ति प्रदान की गई थी। उन्हें अधिनियम की धारा 11 द्वारा अनुध्यात आदेश पारित करने की शक्ति या अधिकार प्रदान किया गया है। हम पहले ही देख चुके हैं

> कि यह कल्पना करना संभव नहीं है कि मुख्य न्यायाधिपति को व्यक्ति पदनाम के रूप में शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए, यह तथ्य कि शक्ति मुख्य न्यायाधिपति को प्रदान की गई है, न कि उनकी अध्यक्षता वाले न्यायालय को, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि इस प्रकार प्रदान की गई शक्ति केवल एक प्रशासनिक शक्ति है और यह न्यायिक शक्ति नहीं है।"

यह स्पष्ट है कि धारा 11 के आवेदनों को परिभाषित "न्यायालय" के समक्ष नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जैसा भी मामला हो, या उनके प्रतिनिधियों के मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष पेश किया जाना है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि मुख्य न्यायाधिपति या उनके प्रतिनिधि को अब न्यायिक रूप से निर्णय लेना है न कि प्रशासनिक रूप से। पुनः, धारा 42 मुख्य न्यायाधिपति या उनके प्रतिनिधि के समक्ष इस साधारण कारण से किए गए आवेदनों पर लागू नहीं होगी कि मुख्य न्यायाधिपति या उनका प्रतिनिधि धारा 2(1) (ई) द्वारा परिभाषित "न्यायालय" नहीं है। उक्त दृष्टिकोण को पांडे एंड कंपनी बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2007) 1 एससीसी 467 में पैराज 9,23-26 में कुछ अलग तरीके से दोहराया गया था।

17. धारा 11 (10) से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जैसा कि मामला हो सकता हैः

> "मुख्य न्यायाधिपति ऐसी योजना बना सकता है जो उसे उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) द्वारा सौंपे गए मामलों से निपटने के लिए उचित लगे।"

इस उप-धारा में निर्दिष्ट योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा मुख्य न्यायाधिपति धारा 11 के तहत अपने द्वारा निस्तारित किये गए मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान कर सकते हैं। यह फिर से दर्शाता है कि यह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नियम नहीं हैं जिनका पालन किया जाना है, बल्कि धारा 11 के प्रयोजनों के लिए मुख्य न्यायाधिपति द्वारा बनाए गए नियमों का एक अलग समूह है।धारा 11 की उप-धारा 12 इस प्रकार हैः

> “(क) जहां उप-धारा (4), उप-धारा (5), उप-धारा (6), उप-धारा (7), उप-धारा (8) और उप-धारा (10) में निर्दिष्ट मामले एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में उत्पन्न होते हैं, उन उप-धाराओं में "मुख्य न्यायाधिपति" के संदर्भ का अर्थ "भारत के मुख्य न्यायाधिपति" के संदर्भ के रूप में किया जाएगा।
>
> (ख) जहां उप-धारा (4), उप-धारा (5), उप-धारा (6), उप-धारा (8) और उप-धारा (10) में निर्दिष्ट मामले किसी अन्य माध्यस्थम में उत्पन्न होते हैं, उन उप-धाराओं में "मुख्य न्यायाधिपति" के संदर्भ का अर्थ उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के संदर्भ के रूप में किया जाएगा, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर धारा 2 की उप-धारा (1) के धारा (ई) में निर्दिष्ट प्रमुख सिविल न्यायालय स्थित है और जहां उच्च न्यायालय स्वयं उस धारा में निर्दिष्ट न्यायालय है, वहां उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।”

यह स्पष्ट है कि धारा 11 (12)(बी) की आवश्यकता इसलिए थी ताकि यह स्पष्ट हो कि "उच्च न्यायालय" का मुख्य न्यायाधिपति केवल ऐसा मुख्य न्यायाधिपति होगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर धारा 2(1)(ई) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय

स्थित है और उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति जिसे धारा 2(1)(ई) में निहित परिभाषा के समावेशी भाग में संदर्भित किया गया है। यह उप-धारा किसी भी तरह से मुख्य न्यायाधिपति या उनके नामित "न्यायालय" को धारा 42 के उद्देश्य के लिए नहीं बनाती है। फिर, मुख्य न्यायाधिपति या उनके पदनाम का निर्णय, जैसा भी मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं होने के कारण, न्यायिक प्राधिकारी का निर्णय होने के कारण इसका कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है, जो अभिलेख न्यायालय नहीं है।

18. अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत दायर आवेदनों के विपरीत, धारा 9 के तहत दायर आवेदन "न्यायालय" के लिए हैं, जैसा कि माध्यस्थम् कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या माध्यस्थम् अधिनिर्णय देने के बाद किसी भी समय अंतरिम आदेश पारित करने के लिए परिभाषित किया गया है, लेकिन इसके प्रवर्तन से पहले। यदि कोई आवेदन किया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, तो किसी विशेष न्यायालय के समक्ष, धारा 42 उस न्यायालय को छोड़कर, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन किया गया है, किसी भी न्यायालय में भाग-I के तहत बाद के सभी आवेदनों को करने से रोकने के लिए लागू होगी।

19. संदर्भ आदेश में जो प्रश्न उठते हैं उनमें से एक यह है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के अर्थ के भीतर एक न्यायालय है। 1940 के अधिनियम के तहत दो निर्णयों, अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य बनाम सेठ और स्केल्टन (पी) लिमिटेड, (1972) 1 एससीसी 702 और गुरु नानक फाउंडेशन बनाम रतन सिंह एंड संस, (1981) 4 एससीसी 634 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि जहां स्वयं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक माध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने माध्यस्थम कार्यवाही पर अपना अधिकार बरकरार रखा था, वहां 1940 के अधिनियम की धारा 2(सी) के उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय "न्यायालय" होगा। ये

निर्णय नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेस्टील एंड फैब्रिकेशंस (पी) लिमिटेड और अन्य (2004) 1 एससीसी 540, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, (2008) 6 एससीसी 732 और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड बनाम कृष्णा ट्रैवल एजेंसी, (2008) 6 एससीसी 741 में दिए गए थे। इन निर्णयों में से पहला 1996 के अधिनियम के तहत एक निर्णय था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब सर्वोच्च न्यायालय एक माध्यस्थ की नियुक्ति करता है लेकिन कार्यवाही पर अपना अधिकार नहीं रखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के अर्थ के भीतर "न्यायालय" नहीं होगा। तीसरे फैसले, गढ़वाल मामले में भी यही स्थिति है। 1940 के अधिनियम के तहत भी, भारत कोकिंग कोल में, वही अंतर किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने माध्यस्थ की नियुक्ति के बाद की कार्यवाही पर अपना अधिकार बरकरार नहीं रखा था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अर्थ के भीतर "न्यायालय" नहीं होगा।

20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 2(1)(ई) में "न्यायालय" की परिभाषा 1940 के अधिनियम की धारा 2(सी) में निहित अपने पूर्ववर्ती से भौतिक रूप से अलग है। इस बात के कई कारण हैं कि उच्चतम न्यायालय को संभवतः धारा 2(1)(ई) के अर्थ के भीतर "न्यायालय" क्यों नहीं माना जा सकता है, भले ही वह माध्यस्थम् कार्यवाही पर अपना अधिकार बनाए रखे। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परिभाषा संपूर्ण है और दो संभावित न्यायालयों में से केवल एक को मान्यता देती है जो धारा 2(1)(ई) के प्रयोजन के लिए "न्यायालय" हो सकती है। दूसरा, 1940 के अधिनियम के तहत, "सिविल न्यायालय" शब्द को एक अपीलीय न्यायालय को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक माना गया है और इसलिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय शामिल होगा जैसा कि 1940 के अधिनियम के तहत उपरोक्त दो

निर्णयों में माना गया था। भले ही यह प्रस्ताव स्वयं संदेह के लिए खुला है, क्योंकि अनुच्छेद 136 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला सर्वोच्च न्यायालय एक साधारण अपीलीय न्यायालय नहीं है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह कारण भी वर्तमान परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जो मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रधान सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय की बात करता है। तीसरा, यदि किसी आवेदन को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ता है, तो अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रदान की गई धारा 9 और 34 के तहत आवेदनों के संबंध में अब तक उपलब्ध अपील उपलब्ध नहीं होगी। अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में कोई और अपील भी उपलब्ध नहीं होगी। एकमात्र अन्य तर्क जो संभवतः दिया जा सकता है वह यह है कि सभी परिभाषा अनुभाग इसके विपरीत संदर्भ के अधीन हैं। धारा 42 का संदर्भ किसी भी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि धारा 42 में "न्यायालय" शब्द को परिभाषित के अलावा अन्यथा समझा जाना चाहिए। धारा 42 का संदर्भ केवल यह देखना है कि मध्यस्थता करार के संबंध में सभी आवेदनों पर अकेले एक न्यायालय की अधिकारिता होगी, जो संदर्भ किसी भी तरह से धारा 42 के अर्थ में सर्वोच्च न्यायालय को "न्यायालय" बनने में सक्षम नहीं बनाता है। यह उचित रूप से कहा गया है कि मंच संयोजकों के नियम को धारा 42 द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। देखें: जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड बनाम जिंदल प्रैक्सेयर ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एससीसी 521 पैरा 59 पर। धारा 42, 1940 अधिनियम की धारा 31(4) से भी स्पष्ट रूप से भिन्न है, जिसमें अभिव्यक्ति "इसे बनाये रखने के लिए सक्षम न्यायालय में बनाया गया है" को धारा 42 में जगह नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि, धारा 2(1}(ई) के तहत, सक्षम न्यायालय को मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले प्रधान सिविल न्यायालय या मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के रूप में तय किया गया है, और किसी अन्य न्यायालय के रूप में नहीं। इन सभी कारणों से, हमारा मानना है कि 1940 अधिनियम के तहत निर्णय 1996 अधिनियम के तहत नहीं

मिलेंगे, और धारा 42 के प्रयोजनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय "न्यायालय" नहीं हो सकता है।

21. एक अन्य प्रश्न जो उत्पन्न हो सकता है वह यह है कि क्या धारा 42 माध्यस्थम् कार्यवाही समाप्त होने के बाद लागू होती है। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि " माध्यस्थम् करार के संबंध में" अभिव्यक्ति व्यापक महत्व के शब्द हैं और माध्यस्थम् कार्यवाही समाप्त होने से पहले या बाद में किए गए सभी आवेदनों में शामिल होंगे। इससे पहले के एक निर्णय, कुंभा मावजी बनाम भारत अधिराज्य, (1953) एससीआर 878 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा था कि क्या 1940 के अधिनियम की धारा 31(4) में "किसी भी संदर्भ में" उपयोग की गई अभिव्यक्ति में वे मामले शामिल होंगे जो माध्यस्थम् कार्यवाही समाप्त होने के बाद हैं और जो एक निर्णय में समाप्त हुए हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "किसी भी संदर्भ में" शब्दों का अर्थ "संदर्भ के क्रम में" नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ "संदर्भ के मामले में" है और यह कि ऐसा वाक्यांश इतना व्यापक और व्यापक है कि माध्यस्थम् पूरी होने और अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद किए गए आवेदन को शामिल कर सकता है। (देखें पैराज 891-893)। जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 42 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति व्यापक रूप से " माध्यस्थम् करार के संबंध में" है और इसमें निश्चित रूप से ऐसे आवेदन शामिल होंगे।

22. धारा 42 के तहत एक और सवाल उठ सकता है कि क्या धारा 42 उन मामलों में लागू होगी जहां न्यायालय में किया गया आवेदन अधिकारिता के बिना पाया जाता है। पुराने अधिनियम की धारा 31(4) के तहत, एफसीआई. प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व और अन्य बनाम ए.एम.अहमद एंड कंपनी एमदी द्वारा प्रतिनिधित्व और अन्य (2001) 10 एससीसी 532 पैरा 6 में और नेयसर इंडिया लिमिटेड बनाम जीएनबी सिरामिक्स लिमिटेड, (2002) 9 एससीसी 489 के पैरा 3 में यह अभिनिर्धारित किया

गया है कि 1940 अधिनियम की धारा 31(4) लागू नहीं होगी यदि यह पाया गया कि एक न्यायालय के समक्ष एक आवेदन किया जाना था जिसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। जतिंदर नाथ बनाम चोपड़ा भूमि विकास प्राइवेट लिमिटेड, (2007) 11 एससीसी 453 पैरा 9 और राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम यूनिवर्सल पेट्रोल केमिकल लिमिटेड, (2009) 3 एससीसी 107 पैरा 33 से 36 और स्वास्तिक गैस (पी) लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 2013 (9) एससीसी 32 पैरा 32 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां पक्षों के बीच करार ने केवल एक विशेष न्यायालय तक ख्सेत्रधिकार को सीमित कर दिया है, अकेले उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा क्योंकि न तो धारा 31(4) और न ही धारा 42 में एक गैर-अबाधित धारा है जो पक्षों के बीच एक विपरीत करार को समाप्त करता है। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकारों द्वारा सहमत विशेष न्यायालय के बाहर के न्यायालयों अदालतों को दिए जाने वाले आवेदन भी अधिकारिता के बाहर होंगे।

23. यहां तक कि धारा 42 के तहत ही एक नामित न्यायाधीश ने एचबीएम प्रिंट लिमिटेड बनाम स्कैनट्रांस इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, (2009) 17 एस. सी. सी. 338, मामले में अभिनिर्धारित किया है कि जहां मुख्य न्यायाधिपति को धारा 11 के तहत कोई अधिकारिता नहीं है, वहां धारा 42 लागू नहीं होगी। यह इस तथ्य से बिल्कुल अलग है कि धारा 42, जैसा कि ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 11 के आवेदनों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगी।

24. यदि किसी आवेदन को किसी ऐसे न्यायालय में प्राथमिकता दी जानी थी जो किसी जिले में मूल अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय नहीं है, या मध्यस्थता के विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करने के लिए मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय में यदि वही विषय रहा हो एक वाद, तो जाहिर तौर पर ऐसा आवेदन धारा 42 के चारों कोनों से बाहर होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई आवेदन

किसी प्रधान सिविल न्यायालय से निचली न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में दायर किया जाना था जिसका कोई मूल अधिकारिता नहीं है, या यदि कोई आवेदन किसी ऐसे न्यायालय में दायर किया जाना था जिसके पास कोई विषय वस्तु क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसा आवेदन धारा 42 के बाहर होगा और बाद के आवेदनों को ऐसे न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में दायर करने से नहीं रोका जाएगा।

25. इसलिए माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई) और धारा 42 पर हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

(क) धारा 2(1)(ई) में एक विस्तृत परिभाषा है जो केवल किसी जिले में मूल अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय या राज्य में मूल सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय को चिह्नित करती है, और माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 के भाग-1 के उद्देश्य के लिए किसी अन्य न्यायालय को "न्यायालय" के रूप में चिह्नित नहीं करती है।

(ख) " माध्यस्थम् करार के संबंध में" अभिव्यक्ति यह स्पष्ट करती है कि धारा 42 1996 के अधिनियम के भाग-1 के तहत माध्यस्थम् कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या अधिनिर्णय दिए जाने के बाद किए गए सभी आवेदनों पर लागू होगी।

(ग) तथापि, धारा 42 केवल भाग-1 के अधीन किए गए आवेदनों पर लागू होती है यदि वे परिभाषित न्यायालय में किए जाते हैं। चूँकि धारा 8 के तहत किए गए आवेदन न्यायिक प्राधिकारियों को किए जाते हैं और चूंकि धारा 11 के तहत आवेदन मुख्य न्यायाधिपति या उनके नामित व्यक्ति को किए जाते हैं, इसलिए न्यायिक प्राधिकारी और मुख्य न्यायाधिपति या उनके नामित व्यक्ति, जो परिभाषित न्यायालय नहीं हैं, ऐसे आवेदन धारा 42 के बाहर होंगे।

(घ) धारा 9 के आवेदन न्यायालय में किए गए आवेदन हैं और धारा 34 के माध्यस्थम् अधिनिर्णयों को अलग करने के लिए आवेदन ऐसे आवेदन हैं जो धारा 42 के भीतर हैं।

(ई) किसी भी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय धारा 2(1)(ई) के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" नहीं हो सकता है, और चाहे सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद सीज़िन रखता है या नहीं रखता है, आवेदन या तो राज्य में मूल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या जिले में मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष किए गए पहले आवेदन का पालन करेंगे।

(च) धारा 42 माध्यस्थम् कार्यवाही समाप्त होने के बाद किए गए आवेदनों पर लागू होगी बशर्ते वे भाग-I के तहत किए गए हों।

(छ) यदि किसी ऐसे न्यायालय में पहला आवेदन किया जाता है जो न तो किसी जिले में मूल अधिकारिता का प्रधान न्यायालय है या किसी राज्य में मूल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय है, तो ऐसा आवेदन धारा 42 के बाहर होगा। इसके अलावा, विषय वस्तु अधिकारिता के बिना न्यायालय में किया गया आवेदन धारा 42 के बाहर होगा।

संदर्भ का जवाब तदनुसार दिया जाता है।

26. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि कैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास अधिकारिता नहीं है। ऊपर उल्लेख किया गया है कि खण्ड 12 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसलिए, वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11 अप्रैल, 2005 का निर्णय सही है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सिविल अपील No.6691/2005 और सिविल अपील No.4808/2013 एतद्द्वारा खारिज किये जाते हैं।

देविका गुजराल

अपीलें खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****